माननीय न्यायमूर्ति डी. बी. लाल और हरबंस लाल के समक्ष

पुष्पा वंती - अपीलकर्ता,
बनाम
माजेसर दास - उत्तरदाता।
1975 की आपराधिक अपील संख्या 56
25 सितंबर, 1978

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का वी) - धारा 256 और 257 - अभियुक्त द्वारा नामित गवाह, जिन्हें अदालत द्वारा तलब नहीं किया गया है - ऐसी बुद्धि की जिरह के लिए निर्धारित तारीख पर अनुपस्थित शिकायत - ऐसी अनुपस्थिति - यदि पर्याप्त हो, आरोपी को बरी करने के लिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 256 से यह स्पष्ट है कि आरोप तय होने और अभियुक्त के बयान दर्ज होने के बाद, अभियुक्त को केवल यह बताने की आवश्यकता है कि वह अभियोजन पक्ष के किन गवाहों से जिरह करना चाहता है। अगर आरोपी यह बताता है और उसके द्वारा गवाहों का नाम लिया जाता है। संहिता की धारा 256 के तहत वह जिनसे जिरह करना चाहता है, तो यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह उन गवाहों को तलब करे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है और यदि किया गया कोई प्रयास फलीभूत नहीं होता है और ऐसे गवाह बाद की तारीखों पर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शिकायतकर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति इन परिस्थितियों में अर्थहीन हो जाती है। गवाहों को तलब करना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो शिकायत को उस आधार पर पीड़ित नहीं किया जा सकता है और आरोपी को केवल इसलिए बरी नहीं किया जा सकता है क्योंकि शिकायतकर्ता को संहिता की धारा 256 के तहत गवाहों से जिरह के लिए निर्धारित तारीख पर अनुपस्थित पाया गया था।

श्री पी. पी. छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बल्लभगढ़ के दिनांक 11 मार्च, 1974 के आदेश से अपील। आरोपियों को बरी कर दिया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता के. डी. सिंह।
प्रतिवादी की ओर से वकील आर. एन. नरूला।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति डी. बी. लाल (मौखिक)-

1) यह आपराधिक अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बल्लभगढ़ के फैसले के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसमें मजेसर दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 504 के तहत अपराधों के लिए बरी कर दिया गया था, इस संक्षिप्त आधार पर कि शिकायतकर्ता श्रीमती पुष्पवंती तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के तहत गवाहों से जिरह के लिए निर्धारित तारीखों में से एक पर अनुपस्थित पाई गई थीं। वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्यों को अब संक्षेप में कहा जा सकता है:
2) पुष्पवंती द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पति शाम लाई आरोपी के घर में किरायेदार थे और बाद में चाहते थे कि वह उस घर को खाली कर दें। तदनुसार 3 मई, 1971 को आरोपी मजेसर दास आया और महिला को घर में अकेला पाकर, उसे गालियां दीं और उसे डंडे से भी पीटा। इस घटना को मोती सिंह और कुछ अन्य लोगों ने देखा था। शिकायत मामले में, पहली तारीख पर शिकायतकर्ता ने अपना बयान दिया और

मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया, उसे दो अपराधों के लिए तलब किया। तत्कालीन संहिता की धारा 252 के तहत शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में अपने गवाह पेश किए। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी की ओर से कुछ जिरह भी की गई थी। हालांकि, संहिता की धारा 254 के तहत एक आरोप तय किया गया था और सीआरपीसी की धारा 255 के तहत आरोपी की याचिका दर्ज की गई थी। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। इसके बाद, मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 256 के मंच पर आया जो निम्नानुसार है:-

"256. (1) यदि अभियुक्त निवेदन करने से इनकार करता है, या दलील नहीं देता है या मुकदमा चलाने का दावा नहीं करता है, तो उसे यह बताना होगा (मामले की अगली सुनवाई के प्रारंभ में या, यदि मजिस्ट्रेट लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उचित समझता है), तो क्या वह किसी से जिरह करना चाहता है, और, यदि हां, जो अभियोजन पक्ष के लिए उन गवाहों में से हैं जिनके साक्ष्य लिए गए हैं। यदि वह कहता है, तो वह ऐसा चाहता है, उसके द्वारा नामित गवाहों को वापस बुलाया जाएगा और जिरह और पुन परीक्षण के बाद (यदि कोई हो), तो उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के लिए किसी भी शेष गवाह के साक्ष्य लिए जाएंगे, और, क्रॉस-एग्जामिनेशन और पुन: परीक्षण (यदि कोई हो) के बाद, उन्हें भी आरोपमुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आरोपी को अपने बचाव में प्रवेश करने और अपने सबूत पेश करने के लिए बुलाया जाएगा।"

3) यदि आरोपी कोई लिखित बयान देता है, तो मजिस्ट्रेट इसे रिकॉर्ड के साथ दायर करेगा। मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिसंबर, 1973 को लिखे गए आदेश पत्र से संकेत मिलता है कि गवाहों से जिरह के लिए मामले को 1 मार्च, 1974 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। ऐसे गवाहों के नाम स्पष्ट रूप से 1 मार्च, 1974 को धारा 256 के तहत आगे की जिरह के लिए अभियुक्तों द्वारा इंगित किए गए थे। मजिस्ट्रेट की अदालत के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि शिकायतकर्ता श्रीमती पुष्पवंती मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव के समक्ष पेश हुई थीं और एक आवेदन दायर किया था, जिसके आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव ने संकेत दिया कि मामला जेएम, आईसी, बल्लभगढ़ को स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्हें 16 मार्च को उस अदालत के समक्ष पेश होना था। 1974. ऐसा हुआ कि 1 मार्च, 1974 को मामला जेएम, आई.सी., बल्लभगढ़ की अदालत में बुलाया गया और शिकायतकर्ता स्पष्ट रूप से उस तारीख को अनुपस्थित पाया गया। आरोपी और उसके वकील मौजूद थे और चूंकि कोई गवाह उपलब्ध नहीं था, इसलिए शिकायतकर्ता के साक्ष्य बंद कर दिए गए। इसके बाद आरोपी के बयान के लिए एक तारीख तय की गई और 11 मार्च, 1974 को, जब शिकायतकर्ता अनुपस्थित था, आरोपी का बयान दर्ज किया गया और उसे अपने बचाव में प्रवेश करने के लिए बुलाया गया। चूंकि उन्होंने बचाव पक्ष के गवाह को पेश नहीं किया, इसलिए बचाव पक्ष को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद, बहस के लिए एक तारीख तय की गई और विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में पाया कि शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहने के कारण गवाहों को जिरह के लिए पेश करने में विफल रहा और इस तरह आरोपी के पास गवाहों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं था। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 257 का हवाला दिया और कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज गवाहों के बयानों को सबूत में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह पाया गया कि कोई मामला नहीं बनता था और आरोपी को बरी कर दिया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट का यह आदेश वर्तमान अपील का विषय-वस्तु है।

4) शिकायतकर्ता अपीलकर्ता के वकील श्री केडी सिंह ने तत्कालीन सीआरपीसी की धारा 256 और 257 का हवाला दिया। सीआरपीसी की धारा 256 से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि आरोप तय होने और आरोपी का बयान दर्ज होने के बाद, आरोपी को केवल यह बताने की आवश्यकता थी कि वह अभियोजन पक्ष के किन गवाहों से जिरह करना चाहता है। यह सभी ने स्वीकार किया है कि आरोपी ने यह बताया था और गवाहों का नाम उसने लिया था, जिन्हें वह सीआरपीसी की धारा 256 के तहत जिरह करना चाहता था। तब मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य था कि वह उन गवाहों

को तलब करे, जो हालांकि नहीं किया गया था या यदि गवाहों को बुलाने का कोई प्रयास किया गया था तो यह फलीभूत नहीं हुआ और मामले का तथ्य यह था कि गवाह बाद की तारीखों पर उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, श्री सिंह का तर्क है, और हमारी राय में यह सही है कि इन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति अर्थहीन थी। यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य था कि वह गवाहों को तलब करे और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो शिकायतकर्ता को उस कारण से पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

5) इस संबंध में, विद्वान मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 257 का हवाला दिया, लेकिन हम इस स्तर पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उक्त धारा केवल आरोपी द्वारा बचाव दर्ज किए जाने के बाद ही लागू होती है। वह चरण अभी तक नहीं आया था और एकमात्र प्रासंगिक धारा सीआरपीसी 256 थी और उस धारा के तहत स्पष्ट रूप से यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य था कि वह गवाहों को तलब करे जो उन्होंने कभी नहीं किया। शिकायतकर्ता को इस आधार पर पीड़ित नहीं किया जा सकता है।
6) यह भी स्पष्ट है कि 1 मार्च, 1974 को शिकायतकर्ता की उपस्थिति के लिए निर्धारित तारीख पर, वह गुड़गांव के समक्ष पेश हुई थी। अदालत ने एक आवेदन दायर किया। उन्हें बल्लभगढ़ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया और 16 मार्च, 1974 की तारीख दी गई। उस तारीख से बहुत पहले ही बल्लभगढ़ अदालत ने संज्ञान ले लिया था और 1 मार्च, 1974 को शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति का पता चलने के बाद, उसका मामला बंद कर दिया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जाना था। यह शिकायतकर्ता के समर्थन में अतिरिक्त आधार है।
7) विद्वान मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 259 के तहत आरोपी को आरोपमुक्त कर सकता था, लेकिन वह आरोप तय होने से पहले ही ऐसा कर सकता था। इस मामले में, आरोप तय होने के बाद का चरण था और इस तरह सीआरपीसी की धारा 259 का कोई उपयोग नहीं था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। इसे अलग रखा जाना चाहिए।
8) विद्वान मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 259 के तहत आरोपी को आरोपमुक्त कर सकता था, लेकिन वह आरोप तय होने से पहले ही ऐसा कर सकता था। इस मामले में, आरोप तय होने के बाद का चरण था और इस तरह सीआरपीसी की धारा 259 का कोई उपयोग नहीं था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। इसे अलग रखा जाना चाहिए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमांशु जांगड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी